एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस
निर्यात लाभ

मार्च 2017
खंड XXXIII अंक I

इस अंक में

1 12वीं सीआईआई-एक्ज़िम बैंक भारत अफ्रीका परियोजना सहभागिता : सतत विकास की ओर
4 राजस्थान से निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं
5 आंध्रप्रदेश से निर्यात बढ़ाने की रणनीतियाँ
7 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
8 तिमाही गतिविधियाँ
9 खाद्य प्रसंस्करण में अंतरराष्ट्रीय व्यापार
11 एक्ज़िम बैंक की गतिविधियां एवं साहित्य समीक्षा
12 एक्ज़िम बैंक का 32वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान
13 सीएलएमवी देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंध बढ़ाना
15 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य
16 व्यापार और भागीदारी अवसर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का
तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

12वीं सीआईआई-एक्ज़िम बैंक भारत अफ्रीका परियोजना सहभागिता : सतत विकास की ओर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) ने विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर 9-10 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में 12वीं सी आई आई-एक्ज़िम बैंक भारत-अफ्रीका परियोजना सहभागिता सम्मेलन का आयोजन किया। भारत-अफ्रीका रणनीतिक सहभागिता के लिए इस व्यवस्थित योजना के विवरण अक्तूबर 2015 में आयोजित तीसरी भारत-अफ्रीका परियोजना सहभागिता सम्मेलन के दौरान जारी किए गए थे। इसका उद्देश्य भारत और अफ्रीका के उद्यमियों, अनुमतिदाताओं को एक मंच पर लाना और इस व्यवस्था को निरंतर जारी रखना था।

पहले सी आई आई-एक्ज़िम बैंक भारत-अफ्रीका परियोजना सहभागिता सम्मेलन का आयोजन 2005 में किया गया था। गत वर्षों में इस सम्मेलन ने न केवल भारत से अफ्रीकी बाजार को परियोजना निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है बल्कि अफ्रीका के उद्यमियों और अनुमतिदाताओं के बीच ब्रांड इंडिया को स्थापित करते हुए भारत की छवि निर्माण में भी योगदान दिया है। भारत-अफ्रीका के बीच बढ़ते परियोजना निर्यात संबंध इस बात का प्रमाण हैं कि इन सम्मेलनों के दौरान होने वाली उच्चस्तरीय चर्चाओं से परियोजना निर्यात को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। पिछले कुछ सालों में यह सम्मेलन भारत-अफ्रीका के बीच सहभागिता को बढ़ाने वाले के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में उभरा है और इसमें प्रत्येक वर्ष अफ्रीका के प्रमुख प्रतिनिधि मंडलों द्वारा शिरकत की जाती है।

इस सम्मेलन का उद्घाटन 9 मार्च, 2017 को माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों को इन वर्षों में काफी मजबूती मिली है और भारत अफ्रीका के साथ एक ऐसी प्रतिबद्ध सहभागिता करने का इच्छुक है जिससे दोनों देशों में रोजगार और अवसरों में वृद्धि हो सके। उन्होंने आगे कहा कि भारत द्वारा अफ्रीका के 40 देशों को 7 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक की ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान की जा चुकी हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत और अफ्रीका का संयुक्त जी डी पी वर्ष 2050 तक 35 ट्रिलियन यू एस डॉलर से अधिक का हो जाएगा और दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या 4 बिलियन के आकड़े को पूरा कर जाएगी; और इस दृष्टि से भारत-अफ्रीका के बीच सहयोग की एक नई इबारत लिखने की जरूरत होगी।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा वर्तमान वैश्विक व्यापार और निवेश परिदृश्य भारत और अफ्रीका के लिए एक बड़े अवसर के रूप में हो सकता है और दोनों ही क्षेत्रों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि 'जब वैश्विक एफ डी आई में 16% की गिरावट आई है उसी समय भारत में व्यापार और निवेश में 30% की वृद्धि हुई है। भारत में एफ डी आई में होने वाली इस वृद्धि का सबसे बड़ा श्रेय 'मेक इन इंडिया' अभियान को जाता है।'

युगांडा की प्रधानमंत्री और सरकारी व्यवसाय प्रमुख ने कहा कि अफ्रीका भारत के साथ कृषि, कृषि प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, हेल्थकेयर और शिक्षा

जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहभागिता का इच्छुक है। उन्होंने भारतीय निवेशकों को अफ्रीका में निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि अफ्रीका में पूर्ण सुरक्षा और स्थायित्व है। इसके अलावा अफ्रीका अपने निवेशकों की संपत्ति और उनके जानमाल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्हें इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है।

स्वाज़ीलैंड के महामहिम राजा म्स्वाती III ने कहा कि भारतीय उद्योग जगत अफ्रीका में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनकी मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने में अफ्रीकी उद्योग की बड़ी मदद कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि विनिर्माण, औषधि और अक्षय ऊर्जा आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश कर भारतीय निवेशक अफ्रीका की सतत प्रगति में काफी मदद कर सकते हैं।

इस कार्यक्रम का समापन 10 मार्च, 2017 को हुआ। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में घाना के प्रधानमंत्री माननीय प्रोफेसर ऐरोन माइक ओक उपस्थित थे। समापन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री श्री एम जे अकबर ने कहा अफ्रीका भारत के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में भी साझेदारी कर सकता है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई अभिनव पहलों जैसे जन-धन योजना, डिजिटल इंडिया और मेक इन इण्डिया को अफ्रीका में भी कार्यान्वित कर सकता है।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर ऐरोन माइक ओक ने कहा कि भारत और अफ्रीका दोनों की ही समान साम्राज्यवादी विरासत रही है और दोनों क्षेत्रों ने ऐतिहासिक रूप से न केवल राजनीतिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी मजबूत सहयोग संबंधों की एक नई इबारत लिखी है। उन्होंने आगे कहा कि अफ्रीका को एक ही चश्मे से देखने के बजाय अफ्रीकी महाद्वीप में मौजूद विविधता को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी साझेदारी है जिसमें अवसरों और लाभों की दृष्टि से दोनों ही क्षेत्रों को फायदा है।

इस अवसर पर भारतीय एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन 'चुनिन्दा पूर्व अफ्रीकी देशों में भारतीय निवेश-अवसर एवं संभावनाएं' का विमोचन सी आई आई-अफ्रीका समिति तथा गोदरेज समूह के अध्यक्ष श्री आदि गोदरेज द्वारा किया गया। इस अवसर पर आई एम एफ में अर्थशास्त्री श्री जिदौद अहमत, एक्ज़िम बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री देबाशिस मल्लिक, पश्चिम अफ्रीकी विकास बैंक (बी ओ डी) उपाध्यक्ष श्री बस्सारी ताउरे, अफ्रीकी विकास बैंक के बाह्य एशिया कार्यालय प्रतिनिधि श्री तदाशी याकोयामा, शापोर जी पल्लोन जी समूह के सलाहकार श्री एस कुप्पुस्वामी तथा

दक्षिण अफ्रीकी विकास बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पैट्रिक डालमानी उपस्थित थे।

इस अध्ययन में पूर्व अफ्रीकी देशों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप इन देशों में भारतीय निवेश के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। पूर्व अफ्रीकी देशों में एफडीआई 2010 से लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2015 में पूर्व अफ्रीकी देशों में बुरुंदी, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, तंजानिया तथा युगांडा का संयुक्त रूप से अफ्रीका के कुल एफ डी आई में 6.4% हिस्सा रहा। विशेष रूप से केन्या, तंजानिया तथा युगांडा उपभोग आधारित निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। पूर्व अफ्रीकी देशों में विशेष रूप से कृषि, बागवानी, विनिर्माण तथा पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए काफी अवसर उपलब्ध हैं। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अब स्थायित्व आ रहा है जिसके चलते अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास मजबूत हो रहा है।

सम्मेलन के दौरान दोनों क्षेत्रों में व्यापार और निवेश को प्रभावित करने वाले विषयों पर सामूहिक चर्चाओं के अलावा द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गईं। यह चर्चाएं मुख्य रूप से विकास सहभागिता, लघु एवं मध्यम उद्यम, कृषि, कौशल विकास, स्वास्थ्य तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, सिंचाई, जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क निर्माण और रेलवे विकास आदि पर केन्द्रित रहीं।

अफ्रीका में बुनियादी सुविधाओं की कमी तथा अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के चलते प्रतिवर्ष जी डी पी वृद्धि को लगभग 2-3% का नुकसान होता है। इसके साथ ही अच्छे सड़क और रेल नेटवर्क की कमी के चलते भी अफ्रीका को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और यह क्षेत्र अपने खनिज संसाधनों का पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। इसी तरह अफ्रीका का ग्रामीण क्षेत्र भी बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते अपनी कृषि उत्पादकता नहीं बढ़ा पाता है। भारतीय उद्योग तथा भारत सरकार मिलकर अफ्रीका में कई महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाओं पर काम कर रहे हैं इनमें सड़कों का निर्माण, रेल-रोड नेटवर्क का निर्माण, बिजली परियोजना, बांध तथा पत्तन आदि हैं। सम्मेलन के दौरान परियोजना विकास, अनुभवों के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण पहलों के जरिए अफ्रीका में भारत द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को रेखांकित किया गया। चर्चाओं के दौरान यह निष्कर्ष निकला कि भारत बुनियादी ढांचे के विकास में अफ्रीका में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है और इसके लिए अफ्रीकी देश बुनियादी ढाँचा निर्माण क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के कौशल और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय कंपनियां भौतिक ढांचे के निर्माण के साथ-साथ परिवहन सुविधा के विस्तार और अफ्रीका में स्मार्ट शहरों के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा सकती हैं।

प्रत्येक सत्र भारत-अफ्रीका सहयोग को मजबूत करने वाले मुद्दों पर केन्द्रित रहा। इन सत्रों में अफ्रीका में भारतीय निवेश बढ़ाने के उपाय, दोनों क्षेत्रों के बीच लंबी अवधि के लिए सहभागिता को मजबूत करना, अफ्रीकी देशों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के उपाय तलाशना, विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने में अफ्रीका की मदद करना, विद्यमान समझौतों/सहयोग करारों के अंतर्गत द्विपक्षीय सम्बन्धों को मजबूत करना, सम्पूर्ण खाद्य सुरक्षा के लिए पूर्व संबंधों को और मजबूत करना, अफ्रीका के बुनियादी ढांचे के विकास में और तेजी लाना और अफ्रीका में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी और तकनीक के क्रियान्वयन के लिए अवसरों को चिन्हित करना आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

भारत-अफ्रीका की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 35% है इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनिबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने के दिशा में किए गए संयुक्त प्रयासों से 2.5 बिलियन लोगों के जीवन में रूपांतकारी परिवर्तन आएगा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत-अफ्रीका दोनों को बुनियादी ढांचे के निर्माण, खाड़ी सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और उनको अंगीकृत करना, हेल्थकेयर और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और अपने सहयोग संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ ही भारत और अफ्रीका को अपने व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तारित करते हुए बहुपक्षीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण की दिशा में भी मिलकर काम करने की जरूरत है।

मोटे तौर पर यदि कहें तो इस सम्मेलन की भूमिका उन उपायों की तलाश करना थी जिनके जरिए भारत अफ्रीकी क्षेत्र में अपनी विकास सहभागी की भूमिका निभा सकता है और अफ्रीका के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सामूहिक नेतृत्व के जरिए इस गृह पर सबके लिए एक सुरक्षित और संपोषी जीवन सुनिश्चित कर सकता है।

सम्मेलन भारतीय और अफ्रीकी कारोबारियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच एक सार्वजनिक व निजी सहभागिता के क्षेत्र में एक संपर्क सूत्र स्थापित करने में सफल रहा। भारत और अफ्रीका के वरिष्ठ मंत्रियों, नीति निर्माताओं और कारोबारी प्रमुखों की उपस्थिति की दृष्टि से यह सबसे बड़े सम्मेलन के रूप में उभरा है जिसमें हर क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच यह सहभागिता न केवल वृद्धि और विकास में सहायक होगी बल्कि भविष्य में भी नए गठबंधनों और सहयोग संबंधों का आधार बनेगी।

4 राजस्थान से निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं

2015-16 में भारत का निर्यात 17 लाख करोड़ रुपए का रहा। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक का रहा। शीर्ष दो राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र का इस निर्यात में करीब 50% योगदान रहा। भौगोलिक रूप से सबसे बड़े राज्य राजस्थान का भारत के निर्यात में लगभग 2% योगदान रहा। राजस्थान में प्राकृतिक खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। श्रम शक्ति भी पर्याप्त संख्या में है और ऐतिहासिक रूप से संपन्न राज्य रहा है। स्पष्ट है, राजस्थान से निर्यात संभावनाओं को अभी पूरी तरह भुनाया नहीं जा सका है।

लंबे तटीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तुलना में राजस्थान की पहुंच बंदरगाह के अभाव में एक विस्तृत बाजार तक नहीं हो पाई। राजस्थान की सीमा छह राज्यों से लगती है और यह देश के उत्तरी हिस्से के विनिर्माण केंद्रों तथा देश के पश्चिमी हिस्सों में बंदरगाहों के बीच एक संपर्क सूत्र का काम करता है। इन दोनों क्षेत्रों से नजदीकी इस राज्य को निवेश के लिए बेहतर स्थल बनाती है और राज्य तथा केंद्र दोनों सरकारें राज्य में उत्पादन बढ़ाने के साथ यहां से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय हैं।

भारत से कुल मर्केंडाइज निर्यात 2008-09 के 8.40 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2015-16 में 17 लाख करोड़ रुपए का हो गया (चार्ट 7)। इसमें 11% की सीएजीआर दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान राजस्थान से निर्यात 13% की सीएजीआर से बढ़कर 2015-16 में 36,04% करोड़ रुपए का हो गया।

यदि हम राजस्थान से निर्यातों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना करें तो 2013-14 को छोड़कर बाकी वर्षों में इसका प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अच्छा रहा है। हालांकि इस वृद्धि दर में बीते तीन वर्षों में गिरावट आई है, जो भारत से निर्यात में गिरावट को प्रदर्शित करती है।

राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पांच मदों में टेक्सटाइल्स (रेडीमेड गारमेंट कपड़ों सहित), रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन और संबंधित उत्पाद (टायरों सहित) और हस्तशिल्प शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में निर्यात की बात की जाए तो राजस्थान में पर्यटन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त, राज्य से सेवा क्षेत्र के निर्यात में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है।

राजस्थान से निर्यात विशाखन

राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और उसे निरंतर बनाए रखना जरूरी है। निर्यात अवसर बढ़ाने का एक रास्ता मूल्य योजन के जरिए निर्यात किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं में विविधता लाना है।

ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें राजस्थान क्षैतिज निर्यात विशाखन के नए उपाय कर सकता है। प्रसंस्कृत खाद्य ऐसा ही एक क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान की सीमित उपस्थिति है। क्षमता निर्माण और क्षैतिज विशाखन के जरिए तैयार भोजन, प्रसंस्कृत खाद्य, सेहतमंद और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों तथा जैविक खाद्य उत्पादों में मूल्य योजन के जरिए यह विशाखन लाया जा सकता है। इन सभी उत्पादों में निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। नुकीले पत्थरों के खंड में देखें तो वर्तमान में कच्चे और रफ ग्रेनाइट, संगमरमर और बलुआ पत्थरों का ही निर्यात किया जाता है। इसमें तराशे हुए ग्रेनाइट और तराशे हुए संगमरमर को शामिल कर निर्यात बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान के निर्यातक रसायन और संबद्ध उत्पाद खंड में भी कृषि रसायन, डाई, टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल होने वाले रंगों वाले रसायनों, निर्माण में काम आने वाले रसायनों और पर्सनल केयर केमिकल जैसे ऊंची कीमत वाले उत्पादों के निर्यात पर जोर दे सकते हैं। इंजीनियरिंग सामान के निर्यातक निर्यात बाजारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग प्लास्टिक खंड पर ध्यान दे सकते हैं। वहीं, टेक्सटाइल क्षेत्र में रेडीमेड गारमेंट और विशिष्ट फैब्रिक पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जो राज्य से निर्यातों को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं।

निर्यातों के वर्टिकल डायवर्सिफिकेशन के लिए भी बहुतायत में अवसर विद्यमान हैं। निर्यातक कृषि और कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात के ऊर्ध्वाधर विशाखन के लिए यूरोपीय संघ, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बड़े और डायनामिक बाजारों का लाभ उठा सकते हैं। वहीं, तराशे हुए पत्थर यूरोपीय संघ, मिस्र, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा के बाजारों में निर्यात किए जा सकते हैं। हस्तशिल्प और कार्पेट खंड से निर्यात राजस्व बढ़ाने के लिए चीन और लैटिन अमेरिकी देशों को लक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा, टेक्सटाइल खंड में निर्यात विशाखन के लक्ष्यों को जापान, अफ्रीका और दक्षिण कोरिया के बाजारों पर फोकस कर हासिल किया जा सकता है।

क्षैतिज और उर्ध्वाधर विशाखन के सुगमीकरण के लिए राज्य के सभी संबंधित हितधारकों को उपयुक्त उपाय करने होंगे। रत्न और आभूषण खंड में तैयार आभूषणों, रंगीन रत्नों, मोतियों, सिंथेटिक रत्नों, कॉस्ट्यूम, फैशन जूलरी और नॉन-गोल्ड जूलरी के निर्यातों के विशाखन के लिए डिजाइन विकास केंद्र की स्थापना करना आवश्यक होगा। पर्यटन राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों और सर्किट हाउसों में बेहतरीन बुनियादी ढांचे का विकास अहम भूमिका निभाएगा। विशेष रूप से एडवेंचर टूरिज्म, ग्रामीण और इको-टूरिज्म तथा अन्य पर्यटन श्रेणियों में संभावनाएं तलाशने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है।

आंध्रप्रदेश से निर्यात बढ़ाने की रणनीतियाँ

आंध्रप्रदेश की अर्थव्यवस्था बहु-आयामी है जिसमें जहां एक ओर लंबा समुद्री तट है जो प्रदेश में विनिर्माण गतिविधियों को मजबूती देता है वहीं दूसरी ओर उपजाऊ नदी बेसिन हैं जो कृषि तथा संबन्धित गतिविधियों का आधार हैं तो वहीं रॉयलसीमा क्षेत्र के जिले खनिज गतिविधियों के लिए उपयुक्त हैं।

समृद्ध संसाधन आधार के साथ सशक्त उत्पादन और मूल्यसंवर्द्धी नेटवर्क के चलते इस राज्य का भारत के निर्यात क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। वर्ष 2015-16 में निर्यात मूल्य की दृष्टि से आंध्रप्रदेश सभी राज्यों में से 6ठे स्थान पर था। राज्य से वस्तुओं का निर्यात देश के कुल निर्यात में 6% हिस्से के साथ 794 बिलियन यू एस डॉलर का रहा।

भारत वर्ष 2020 तक विश्व निर्यात में अपना हिस्सा 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5% करना चाहता है। जो सभी राज्यों से निर्यातों में वृद्धि से ही संभव हो सकता है। देश के इन लक्ष्यों को देखते हुए आंध्रप्रदेश से वर्ष 2020 तक निर्यात 25 बिलियन यू एस डॉलर होना चाहिए। इसी प्रकार देश के कुल निर्यात में 7.5% का हिस्सा रखने के लिए आंध्रप्रदेश से वर्ष 2020 तक निर्यात 39 बिलियन यू एस डॉलर होना चाहिए। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य को व्यापार प्रतिस्पर्द्धा पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए नवोन्मेष बढ़ाने, निर्यात वित्त के उपलब्धता सुनिश्चित करना, निर्यातों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना आदि प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक रोडमैप और कार्य-योजना बनाने हेतु निम्नलिखित निर्यात रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं।

वेयरहाउस और भंडारण सुविधाओं में वृद्धि

समुचित परिवहन, भंडारण और वितरण सुविधाओं की कमी पूरे देश में निर्यातकों के सामने एक प्रमुख मुद्दा है। आंध्रप्रदेश में यह एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि यहाँ के निर्यात में जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का बड़ा हिस्सा है। एक्ज़िम बैंक के विश्लेषण के अनुसार कृषि और कृषि आधारित निर्यात की ही बात करें तो प्रदेश के पास कम से कम 19 मिलियन टन की भंडारण सुविधा होनी चाहिए किन्तु आंध्रप्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग निगम द्वारा सूचित किए गए अनुसार इसकी तुलना में राज्य के पास केवल 1.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष की ही भंडारण सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज की अत्यंत आवश्यकता है।

जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए राज्य को मल्टी-मॉडल (बहुस्तरीय) कोल्ड चेन नेटवर्क प्रणाली अपनाने की जरूरत है। इसमें दो या दो से अधिक परिवहन प्रणालियों और स्टोरेज नेटवर्क का उपयोग कर उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इस प्रस्तावित मल्टी-मॉडल नेटवर्क का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना होना चाहिए।

तटीय विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना

देश की सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 14 तटीय विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 2 तटीय विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना आंध्रप्रदेश में प्रस्तावित है। इनमें से एक काकीनाड़ा, वाइज़ैग और गंगावरम के पोर्टों को कवर करेगा जबकि दूसरा कृष्णपट्टनम पोर्ट को कवर करेगा। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं की स्थापना के साथ-साथ सरकार द्वारा इनमें स्थित उद्यमों के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होगी। इससे होने वाले निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रमुख संवाहकों को चिन्हित कर इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही अपेक्षित नीतिगत परिवर्तनों में उद्यमों के स्वरूप और इसके विकास के चरण और निर्यात मात्रा के आधार पर करों में छूट निर्धारित करना, संयुक्त परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं की स्थापना करना, और इन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की बिक्री के कुछ प्रतिशत को कम टैरिफ दरों पर घरेलू बाज़ारों में बेचने की छूट प्रदान करना आदि प्रमुख हैं।

आंध्रप्रदेश निर्यात विकास परिषद (एपीईपीसी) की स्थापना

राज्य सरकार, उद्योग संगठनों और निर्यातकों के सहयोग से आंध्रप्रदेश निर्यात विकास परिषद की स्थापना की जा सकती है जो निर्यातकों को इस क्षेत्र में जरूरी सूचनाएँ मुहैया कराने के साथ-साथ उनका मार्गदर्शन कर सकती है। परिषद राज्य सरकार और निर्यातकों के बीच एक लिंक के रूप में काम करेगी और निर्यात वृद्धि में आने वाली समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इसी तरह से कच्चे माल की समय पर और निर्बाध आपूर्ति के लिए टेक्सटाइल, इंजीनिरिंग, कृषि और खाद्य उत्पाद क्षेत्रों में उद्योग विभाग, आंध्रप्रदेश सरकार के सहयोग से कच्चे माल के बैंक स्थापित किए जा सकते हैं। यह बैंक एम एस एम ई इकाइयों को उनकी आवश्यकतानुसार कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और कच्चे माल के मूल्यों में बड़ी घट-बढ़ से इन छोटी इकाइयों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पास एक निश्चित भंडार बनाए रख सकते हैं। इस संबंध में आंध्रप्रदेश निर्यात विकास परिषद निर्यात उन्मुख इकाइयों को आने वाली आपूर्ति संबंधी समस्याओं का आकलन कर राज्य सकार से अपनी अनुशंसाएं कर सकती है।

उत्पादों की जीआई ब्रांडिंग करवाना

आंध्रप्रदेश के कई हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम उत्पादों को जीआई स्टेटस प्राप्त है। इन उत्पादों के लिए विशिष्ट मूल्यवर्द्धक दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने जरूरी हैं; जैसे इन उत्पादों का नाम और लोगो डिजाइन करवाकर, उनकी मार्केटिंग करवाकर जी आई ब्रांडिंग को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जी आई ब्रांडिंग के अंतर्गत आने वाले उत्पाद निर्धारित न्यूनतम गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हों। साथ ही राज्य से अन्य नए उत्पादों को चिन्हित कर उनके लिए स्टेटस प्राप्त किया जाए। इसके लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ब्रांड ईक्विटी फंड बनाया जाना चाहिए। इस फंड का उद्देश्य आंध्रप्रदेश के उत्पादों के लिए एक

प्रतिस्पर्द्धी वैश्विक ब्रांड का निर्माण करना होगा। यह फंड अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रदेश की ब्रांडेड उत्पादों की मार्केटिंग करने में भी मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रदेश के ब्रांडेड उत्पादों की पहुँच बढ़ाने के लिए निर्यात संबंधी उपयुक्त ब्रोशर, सी डी और अन्य सामग्री का निर्माण किया जाना चाहिए।

निर्यात पुरस्कार

राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिए पुरस्कार की स्थापना की जानी चाहिए ताकि सभी प्रमुख क्षेत्रों – जैसे कृषि एवं संबन्धित उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन एवं संबन्धित उत्पाद, इंजीनियरी उत्पाद, वस्त्र एवं परिधान, दवा एवं औषधि तथा सेवा क्षेत्र आदि में सफल निर्यातकों के प्रयासों को सराहा जा सके। इसके साथ ही राज्य की निर्यातक एम एस एम ई इकाइयों के लिए अलग से पुरस्कार की स्थापना की जा सकती है।

कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण

राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबन्धित विभिन्न विषयों पर सभी क्षेत्रों के लिए नियमित आधार पर कार्यशाला, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाने आवश्यक हैं। विभिन्न औद्योगिक संगठन, एजेंसियाँ और प्रस्तावित निर्यात विकास परिषद इन कार्यक्रमों के आयोजन में मदद कर सकती हैं।

राज्य सरकार को राष्ट्रीय क्षेत्र विशिष्ट कौशल परिषद की तर्ज पर राज्यस्तरीय क्षेत्र विशिष्ट कौशल परिषदों का गठन किया जा सकता है। इनका कार्य विद्यमान क्षमताओं का उपयोग करते हुए निर्यातकों की क्षमताओं में और विस्तार करने सहित विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं पर जानकारी प्रदान करना होगा।

तकनीकी व्यापार बाधाओं/मानकों के समाधान के लिए वित्तीय सहयोग

विकसित देशों में नॉन टैरिफ तकनीकी बैरियर्स निर्यातकों को इन बाज़ारों में पहुँचने से हतोत्साहित करते हैं। आन्ध्रप्रदेश के लिए इन बैरियर्स से निपटना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ के निर्यात में कृषि एवं संबन्धित उत्पादों की प्रधानता है जिसे अधिकांश राष्ट्रों द्वारा संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए मानदंड काफी कड़े हैं और इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत होती है। निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार अनिवार्य प्रमाणन पर आने वाले खर्चों को वहन कर सकती है। निर्यातक इकाई के कारोबार के आधार पर 50-100 प्रतिशत तक अनिवार्य प्रमाणन/अनुपालन पर आने वाले खर्च को सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है।

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण योजनाओं का फायदा उठाना

भारत सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएँ चलाई गई हैं जहां वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा हासिल करने के लिए नई तकनीक/प्रौद्योगिकी को खरीदने के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जा सकती है। आर एफ पी चक्र के खुलने से पहले ही राज्य सरकार निर्यातक कंपनियों/क्लस्टरों से आवेदन मंगाकर उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फार्मों/आवेदनों की समीक्षा कर सकती है और उनमें जरूरी सुधार के लिए सलाह सहित आवेदन भरने के लिए वित्तीय सहायता भी दे सकती है। चूंकि इन योजनाओं के अंतर्गत खरीदी जाने वाली तकनीकी/प्रौद्योगिकी की लागत का केवल कुछ प्रतिशत ही प्राप्त होता है इसलिए राज्य सरकार मामलेवार आधार पर अपनी ओर से भी अतिरिक्त सहायता देने पर विचार कर सकती है।

एक्ज़िम बैंक से सहयोग

एक्ज़िम बैंक के कई प्रमुख कार्यक्रम जैसे ऋण-व्यवस्थाएँ (एल ओ सी), बी सी एन ई आई ए क्रेता ऋण आदि राज्य से लंबी और मध्यम अवधि के निर्यात बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और इनके जरिए भारतीय कंपनियों को कई नए निर्यात अवसर मिल सकते हैं। ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के जरिए आंध्रप्रदेश के निर्यातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकते हैं। जैसे सीमेंट क्षेत्र में बैंक द्वारा जिबूती, डी आर कोंगो, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, तथा कोंगो गणराज्य को कई ऋण-व्यवस्थाएँ दी गई हैं जो अभी परिचालनरत हैं। आंध्रप्रदेश के निर्यातक इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

चूँकि राज्य द्वारा कई प्रौद्योगिकी गहन उत्पादों का भी निर्यात किया जाता है इसलिए राज्य को इस क्षेत्र में उत्पादों की प्रौद्योगिकी गहनता बढ़ानी होगी। चूँकि शोध एवं विकास कार्यों में बड़े निवेश की आवश्यकता होती है और इनसे प्रतिफल काफी लंबे समय के बाद मिलता है इसलिए कंपनियाँ बैंक के विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च और आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर इस क्षेत्र में सीधे अपनी बढ़त बना सकती हैं। इसके साथ ही आंध्रप्रदेश के निर्यातक अपने विदेशी निवेश के जरिए वर्टिकल इंटीग्रेशन कर अपनी कार्यकुशलता और लाभ मार्जिन बढ़ा सकते हैं।

आंध्रप्रदेश से मशीनरी निर्यात की भी काफी संभावनाएं हैं। किन्तु यह संभावनाएं इस मामले में सीमित हैं कि अधिकांश भारतीय परियोजना निर्यातों का बाजार विकसित देश ही हैं जो लंबी और मध्यम अवधि की उधारी पर ही परियोजना निर्यातों की मांग करते हैं। बैंक के बीसी एनईआईए क्रेता ऋण कार्यक्रम का लाभ उठाकर निर्यातक कई नए देशों में बाजार संभावनाएं तलाश कर अपने निर्यातों का विशाखन कर सकते हैं।

क्षमता निर्माण एवं औद्योगिक क्लस्टर

राज्य के औद्योगिक क्लस्टरों का उन्नयन और विकास राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए पहले कदम के रूप में राज्य में उपलब्ध औद्योगिक क्लस्टरों का समग्र मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। सरकार द्वारा यह मूल्यांकन इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी अवरोध, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता, पर्यावरण पर प्रभाव आदि मुद्दों पर फोकस करते हुए किया जाना चाहिए। क्लस्टरों के मूल्यांकन के बाद इनमें अपेक्षित अनुसार क्षमता निर्माण प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। क्षमता निर्माण प्रक्रिया में शामिल प्रमुख मुद्दों में भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, संस्थाओं का निर्माण और मानव संसाधन विकास आदि हो सकते हैं।

एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मध्यम उद्यमों पर विशेष बल के साथ भावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण–व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है। ये ऋण–व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातक समुदाय को जोखिम और दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं, जो उन्हें नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने और मौजूदा विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने में मदद करती हैं। एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण–व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है।

हाल के वर्षों में ऋण–व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं।

बैंक अब अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका ओशिनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 63 देशों को 15.88 अरब यूएस डॉलर की 215 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान कर चुका है, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण–व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से जनवरी–मार्च 2017 की अवधि के दौरान निम्नलिखित दो ऋण–व्यवस्था करारों पर हस्ताक्षर किए:

I). केन्या सरकार को 100.00 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की है। यह ऋण–व्यवस्था केन्या में कृषि यंत्रीकरण के लिए प्रदान की गई है। इस ऋण–व्यवस्था सहित भारत सरकार की ओर से एक्ज़िम बैंक द्वारा केन्या को अब तक 206.55 मिलियन यूएस डॉलर की चार ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इससे पहले की ऋण–व्यवस्थाएं केन्या में बिजली ट्रांसमिशन लाइन के वित्तपोषण, रिफ्ट वैली टेक्सटाइल्स फैक्टरी (रिवाटेक्स ईस्ट अफ्रीका लि.) के उन्नयन तथा विभिन्न 7 लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रदान की गई हैं।

II). गयाना सरकार को 4 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण–व्यवस्था उच्च क्षमता वाले फिक्स्ड एवं मोबाइल ड्रेनेज पम्पों को खरीदने तथा संबद्ध संरचनाओं के लिए प्रदान की गई है। चार मिलियन यूएस डॉलर की इस ऋण–व्यवस्था सहित भारत सरकार की ओर से एक्ज़िम बैंक द्वारा गयाना सरकार को अब तक 92.38 मिलियन यूएस डॉलर की कुल सात ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। गयाना सरकार को प्रदान की गई अन्य ऋण–व्यवस्थाओं में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापना, सिंचाई पंपों की आपूर्ति, अस्पताल, सड़क निर्माण परियोजना तथा यात्री मालवाहन फेरी वेसल की आपूर्ति जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

तंजानिया – तंजानिया में अपर रूवु जलशोधन संयंत्र का विस्तार

एक्ज़िम बैंक द्वारा तंजानिया सरकार को तंजानिया में दार-अस-सलाम और शालिंज इलाकों में जल आपूर्ति योजनाओं को सुचारू बनाने के लिए 178.125 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यंवस्था प्रदान की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत रुवु नदी जल में पानी की आवक को बढ़ाकर 210 मिलियन लीटर प्रतिदिन करना, म्लांदिजी में अपर रुवु जल शोधन संयंत्र की शोधन क्षमता को बढ़ाकर 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन करना और 130 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला नया जल शोधन संयंत्र स्थापित करना तथा किबाम्बा और किमारा जलाशयों में 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल आपूर्ति क्षमता वाले पंपिंग सेट इंस्टॉल करना शामिल था।

अपर रुवु जल आपूर्ति व्यवस्था की जल उत्पादन एवं वितरण क्षमता में वृद्धि कर जल आपूर्ति को प्रतिदिन 82 मिलियन लीटर से बढ़ाकर 200 मिलियन लीटर किया गया। इससे दार-अस-सलाम क्षेत्र के लोगों के लिए जल आपूर्ति बढ़ी। पहला चरण परिचालन में है तथा दार-अस-सलाम के 2 मिलियन लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

अधिक जानकारी के लिए
कृपया संपर्क करें :

श्री नदीम पंजेतन,
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात–आयात बैंक,
मेकर चेंबर्स IV, 8वीं मंज़िल,
222 नरीमन पॉइंट, मुंबई– 400 021.
टेलीफोन : (22) 22861561
फैक्स : (22) 22823394
ई–मेल : eximloc@eximbankindia.in

एक्ज़िम बैंक ने शुरू किया 'एक्ज़िम मित्र' पोर्टल

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' अभियान की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जो बैंक के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। एक ओर जहां इस पोर्टल पर निर्यात को सुगम बनाने वाले वित्तीय उत्पादों की सूचनाएं मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर व्यापार से जुड़ी जानकारियां भी मुहैया कराई जाएंगी। बैंक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है ***'एक्ज़िम मित्र'*** (www.eximmitra.in), यानी निर्यातकों और आयातकों का दोस्त। एक्ज़िम मित्र ऐसे निर्यातकों और आयातकों को प्राथमिक सहयोग प्रदान करेगा, जिन्हें व्यापार से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारियां किसी एक जगह नहीं मिल पाती हैं। एक्ज़िम मित्र निर्यात के लिए संभावित वैश्विक बाजारों और उत्पादों का पता लगाने के लिए प्रवेश द्वार का काम करेगा और इसके जरिए निर्यातकों को उत्पादों के वैश्विक मानक तथा अनुमानित ढुलाई लागत आदि जानने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस पोर्टल पर निर्यातकों और आयातकों के लिए उपलब्ध विभिन्न ऋण तथा बीमा सुविधाओं की जानकारी सहित अन्य वेल्यू एडेड सेवाओं के साथ हैंडहोल्डिंग प्रदान करने वाली एजेंसियों की जानकारी भी मिलेगी। एक्ज़िम बैंक की यह पहल कंपनियों, खास तौर पर लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लाभदायक होगी और इससे उन्हें विदेशों में अपने कारोबार का विस्तार करने के संबंध में निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

एक्ज़िम बैंक ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत कोत दि'वार सरकार को दिया 87.46 मिलियन यूएस डॉलर का क्रेता ऋण

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा 500 बसों, 62 फ्लीट मेंटेनेंस सपोर्ट वाहनों, कल पुर्जों और संबंधित सेवाओं की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के अंतर्गत कोत दि'वार सरकार को 87.46 मिलियन यूएस डॉलर का क्रेता ऋण प्रदान किया। इस संबंध में बीसी- एनईआईए करार पर आबिदजान, कोत दि'वार में 28 दिसंबर, 2016 को हस्ताक्षर हुए। इस करार पर कोत दि'वार सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री के आर्थिक तथा वित्त प्रभारी श्री आदामा कोने और एक्ज़िम बैंक की ओर से आबिदजान प्रतिनिधि कार्यालय के निवासी प्रतिनिधि श्री पुष्पेश त्यागी द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन ने आसियान क्षेत्र के संदर्भ में सीएलएमवी देशों के साथ भारत के व्यावसायिक संबंध बढ़ाने की रणनीतियाँ बताईं

एक्ज़िम बैंक का प्रकाशन 'सीएलएमवी देशों के साथ भारत के व्यावसायिक संबंधः आसियान बाजारों का प्रवेश द्वार' राजस्थान के जयपुर में 27 फरवरी, 2017 को हुई चौथी इंडिया-सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव के दौरान जारी किया गया। आसियान क्षेत्र के सीएलएमवी (कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम) देशों में भविष्य में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए वैश्विक आर्थिक समुदाय का आकर्षण इस ओर बढ़ना शुरू हो गया है। आसियान क्षेत्र में भारत के आर्थिक हित भी बीते कुछ वर्षों में बढ़े हैं। हमारा 'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' नीति की ओर बढ़ना इसका प्रमाण है। आसियान क्षेत्र में भी विशेष रूप से सीएलएमवी देशों में आर्थिक विकास अलग-अलग स्तरों पर है। विकास के अंतर को कम करते हुए अन्य आसियान देशों के साथ सीएलएमवी देशों का एकीकरण करना वर्तमान में आसियान समुदाय की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इस क्षेत्र में विस्तृत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, विकास के अंतर को कम करने और सीएलएमवी देशों को आसियान क्षेत्र की अन्य छह विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समकक्ष खड़ा करने के लिए सहयोग के तरीके में थोड़ी विविधता लाना जरूरी है। इसके लिए सीएलएमवी देशों में विकासात्मक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मसलन- परिवहन, ऊर्जा, टेलीकम्यूनिकेशन, पर्यावरण, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, व्यापार और कृषि तथा अन्य विकासात्मक क्षेत्र शोध अध्ययन में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में अवसर तो बहुतायत में हैं, लेकिन इन देशों में भारतीय उद्यमियों के प्रयास सीमित हैं। शोध अध्ययन में आसियान के संदर्भ में सीएलएमवी देशों में भारत के व्यावसायिक संबंध बढ़ाने के लिए प्रमुख रणनीतियों को रेखांकित किया गया है। इनमें कृषि क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन विकास, वित्तीय सेवाओं, आईटी आधारित सेवाओं, क्षेत्रीय वेल्यू चेन, कनेक्टिविटी में सुधार और एसएमई क्षेत्र में सहयोग कुछ प्रमुख रणनीतियां हैं, जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। इसके साथ ही निवेश को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों/ वाणिज्य संगठनों जैसी संस्थाओं से संबंध विकसित करने जैसी रणनीतियों का भी विशेष उल्लेख किया गया है।

एक्ज़िम बैंक ने कैमरून सरकार को राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत 93.50 मिलियन यूएस डॉलर का क्रेता ऋण प्रदान किया

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत कैमरून सरकार को 93.50 मिलियन यूएस डॉलर का क्रेता ऋण प्रदान किया। यह क्रेता ऋण कोंगसाम्बा-बाफौसाम और याओंडे-अबोंग बैंग तक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए प्रदान किया गया है। इस संबंध में बीसी-एनईआईए करार पर 2 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इस करार पर एक्ज़िम बैंक की ओर से उप प्रबंध निदेशक श्री देबाशिस मल्लिक और कैमरून सरकार की ओर से माननीय अर्थव्यवस्था, योजना और क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री मोताज़े लुई पॉल ने हस्ताक्षर किए।

अफ्रीका के विकास के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण हैं भारत के अनुभवः अध्यक्ष, अफ्रीकी विकास बैंक

अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) के अध्यक्ष डॉ. अकिनूमी एडिसिना ने भारत और अफ्रीका के बीच विभिन्न स्तरों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से सरकार, व्यवसाय से व्यवसाय और एएफडीबी एवं भारतीय एक्ज़िम बैंक के बीच मौजूद सहयोग फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत स्तरों पर यह सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। भारतीय कारोबारी समुदाय के साथ एक्ज़िम बैंक की ओर से आयोजित चर्चा सत्र में डॉ. एडिसिना ने कहा कि एएफडीबी ने अगले 10 साल में अफ्रीका के कायापलट के लिए पांच प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है- रोशन और ऊर्जाक्षम अफ्रीका, पोषित अफ्रीका, उद्योगमय अफ्रीका, एकीकृत अफ्रीका और बेहतर जीवनशैली वाला अफ्रीका। भारत को इन सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है, जो अफ्रीकी महाद्वीप के इस कायापलट में मदद कर सकता है।

एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना ने एएफडीबी के अध्यक्ष डॉ. अकिनूमी एडिसिना के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि एक्ज़िम बैंक का मानना है कि अफ्रीका में भारतीय कंपनियों के लिए अच्छे अवसर विद्यमान हैं, विशेष रूप से ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में। श्री रस्कीना ने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में एक्ज़िम बैंक ने अफ्रीका को 3.61 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं, जो कुल ऋण प्रतिबद्धताओं की करीब आधी यानी 50% हैं।

एक्ज़िम बैंक ने हाल ही में 'प्रसंस्कृत खाद्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापारः भारतीय परिप्रेक्ष्य' शीर्षक से एक शोध अध्ययन प्रकाशित किया है। इसमें भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन कारणों की तलाश करने का प्रयास किया गया है, जिनके चलते प्रसंस्कृत खाद्य के विश्व व्यापार में भारत का सीमित हिस्सा है, जबकि भारत सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है। इस आलेख में इस शोध अध्ययन का सार प्रस्तुत है।

क्षेत्रवार विश्लेषण

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात 12.9 अरब यूएस डॉलर का रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17.3% की गिरावट दर्ज की गई। भारत से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अग्रणी निर्यात स्थल वियतनाम रहा, जिसे देश के कुल प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का 22.6% निर्यात किया गया। अन्य निर्यात स्थलों में अमेरिका (15%), संयुक्त अरब अमीरात (4.8%), मलेशिया (4.6%), सऊदी अरब (3.4%), जापान (3.4%), मिस्र (3.1%), थाईलैंड (2.5%), यूके (2.1%) और इंडोनेशिया (2.0%) शामिल रहे।

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य का आयात 1.3 अरब यूएस डॉलर का रहा। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में न तो इसमें गिरावट आई और न ही कोई बढ़ोत्तरी हुई। भारत के लिए प्रसंस्कृत खाद्य का अग्रणी आयात स्रोत यूके रहा, जिससे भारत ने कुल प्रसंस्कृत खाद्य का 16.8% आयात किया। अन्य प्रमुख आयात स्रोतों में अमेरिका, नेपाल, चीन, इंडोनेशिया, फ्रांस, सिंगापुर, ब्राजील, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात रहे।

खंडवार विश्लेषण

फल और सब्जियां

2015-16 में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का भारत का निर्यात 856.7 मिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें बीते वर्ष की तुलना में 4% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। 2015-16 में भारत से प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का प्रमुख निर्यात स्थल अमेरिका रहा, जिसे प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के कुल निर्यात का 14.4% निर्यात किया गया। सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल रहा, जिसे 81.5 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया। इसके बाद प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के लिए प्रमुख निर्यात स्थलों में नीदरलैंड (8.3%), यूके (8.1%), जर्मनी (5.4%), संयुक्त अरब अमीरात (5.2%), रूस (3.7%), फ्रांस (3.6%), बेल्जियम (3.4%) और कनाडा (2.8%) शामिल रहे।

2015-16 के दौरान भारत द्वारा प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का आयात 99.9 मिलियन यूएस डॉलर रहा। प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का भारत के लिए प्रमुख आयात स्रोत चीन रहा। इसके बाद अमेरिका और अफगानिस्तान का स्थान रहा।

मत्स्य उत्पाद

वर्ष 2015-16 के दौरान मत्स्य और समुद्री खाद्य पदार्थों (सीफूड) में भारत का अधिशेष (सरप्लस) दर्ज किया गया। इस खंड में भारत का निर्यात 4696.6 मिलियन यूएस डॉलर का रहा और आयात 67.7 मिलियन यूएस डॉलर दर्ज किया गया। 2015-16 के दौरान भारत से प्रसंस्कृत मत्स्य उत्पादों और समुद्री खाद्य का प्रमुख निर्यात स्थल अमेरिका रहा, जिसने इस खंड में भारत के कुल निर्यात का 28.2% अकेले ही आयात किया। 885.6 मिलियन यूएस डॉलर के आयात के साथ वियतनाम दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा। भारत से प्रसंस्कृत मत्स्य उत्पादों और समुद्री खाद्य के अन्य प्रमुख निर्यात स्थलों में जापान (8.5%), स्पेन (3.9%), बेल्जियम (3.7%), चीन (3.1%), संयुक्त अरब अमीरात (3.0%), यूके (2.9%), इटली (2.7%) और थाईलैंड (2.7%) शामिल रहे।

2015-16 के दौरान भारत को प्रसंस्कृत मत्स्य उत्पादों और समुद्री खाद्य का सबसे बड़ा निर्यातक रहा। इस खंड में भारत के अन्य प्रमुख आयात स्रोतों में वियतनाम, अमेरिका, म्यांमार, यूके, ओमान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर शामिल रहे।

प्रसंस्कृत दूध, मांस, पोल्ट्री और अंडे

दूध

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत से डेयरी उत्पादों का निर्यात 115.3 मिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 41% की मोटी गिरावट दर्ज की गई। 27.6 मिलियन यूएस डॉलर के आयात (23.9%) के साथ संयुक्त अरब अमीरात, भारत से डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यात स्थल रहा। 2015-16 के दौरान पाकिस्तान डेयरी उत्पादों के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल रहा, जिसे डेयरी उत्पादों के निर्यात का कुल 16.1% निर्यात किया गया। भारतीय डेयरी उत्पादों के अन्य प्रमुख निर्यात स्थलों में बांग्लादेश, सिंगापुर, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान शामिल रहे।

2015-16 के दौरान भारत द्वारा डेयरी उत्पादों का आयात 49 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। फ्रांस, भारत के लिए डेयरी उत्पादों का प्रमुख आयात स्रोत रहा, जिससे कुल डेयरी उत्पादों के आयात का लगभग 27.5% आयात किया गया। अन्य प्रमुख आयात स्रोतों में न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड और युगांडा शामिल रहे।

मांस

भारत दुनिया के सबसे बड़े मांस निर्यातकों में से एक है। 2015-16 के दौरान भारत से 4201 मिलियन यूएस डॉलर का मांस निर्यात किया गया। भारत से मांस निर्यात के लिए प्रमुख निर्यात स्थल वियतनाम रहा, जिसे भारत से कुल मांस निर्यात का 47.4% निर्यात किया गया। 410 मिलियन यूएस डॉलर के आयात के साथ मलेशिया दूसरा सबसे बड़ा मांस आयातक देश रहा। इसके बाद भारत के लिए प्रमुख मांस निर्यात स्थलों में मिस्र (8.5%), सऊदी अरब (5.8%), संयुक्त अरब अमीरात (4.4%), इराक (2.8%), फिलीपींस (2.8%), अल्जीरिया (2.7%), थाईलैंड (2.6%) और कुवैत (2.3%) शामिल रहे।

2015-16 के दौरान भारत द्वारा 3.8 मिलियन यूएस डॉलर का मांस आयात किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आयात में 28.8% की गिरावट दर्ज की गई। 2015-16 के दौरान भारत में मांस आयात के लिए श्रीलंका सबसे बड़ा आयात स्रोत रहा, जिससे भारत के कुल मांस आयात का 23.2% आयात किया गया। इसी अवधि के दौरान अन्य प्रमुख आयात स्रोतों में बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्पेन, इटली, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी और थाईलैंड शामिल रहे।

पोल्ट्री और अंडे

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत से पोल्ट्री और अंडों का निर्यात 117 मिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें 10.9% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। 2015-16 के दौरान भारत से पोल्ट्री और अंडों के निर्यात के लिए प्रमुख निर्यात स्थल ओमान रहा, जिसे 31 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया, जिसका हिस्सा भारत से पोल्ट्री और अंडों के कुल निर्यात का 26.5% रहा। 12.5% हिस्से के साथ सऊदी अरब पोल्ट्री और अंडों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा। भारत के लिए पोल्ट्री और अंडों के अन्य प्रमुख निर्यात स्थलों में जापान, जर्मनी, मालदीव, बहरीन और इंडोनेशिया शामिल रहे, निर्यात में जिनका हिस्सा क्रमशः 10.5%, 7.6%, 6.9%, 6.4% और 5.9% रहा।

जहां तक आयात का सवाल है तो 2015-16 के दौरान भारत द्वारा पोल्ट्री और अंडों का प्रमुख आयात स्रोत जर्मनी रहा। भारत द्वारा पोल्ट्री और अंडों के कुल आयात का 80.5% अकेले जर्मनी द्वारा ही आयात किया गया।

शोध अध्ययन का निष्कर्ष

शोध अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि देश का न्यून कृषि उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में प्रमुख बाधा है। कृषि क्षेत्र को सिंचाई और जल प्रबंधन के अलावा अनुसंधान एवं विकास में बेहद सीमित प्रयासों और महंगी विस्तार सेवाओं जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। शोध अध्ययन में संकेत किया गया है कि विकसित देशों को निर्यात किए जाते समय भारतीय कृषि उत्पादों को नामंजूरी का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भारतीय कृषि उत्पादों में उर्वरकों और कीटनाशकों का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है तथा श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों (जीएपी) का सीमित इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त, नए खाद्य संरक्षा नियम लागू होने के बावजूद खाद्य उद्योग में नियमों और विनियमों को लेकर संवाद और सुगठित ढांचे संबंधी अस्पष्टता बनी हुई है।

अध्ययन के अनुसार, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा अपर्याप्त कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि उत्पादों की बर्बादी, बुनियादी ढांचागत मसले, कृषि उत्पादों में अपर्याप्त मूल्य वर्धन, वित्त की सीमित उपलब्धता, कर ढांचा, कुशल श्रमशक्ति की कमी और नवोन्मेष के अभाव जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

इस क्षेत्र के विकास की इन बाधाओं से पार पाने के लिए अध्ययन में कुछ रणनीतियां सुझाई गई हैं, ताकि इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ाई जा सकें और बेहतर प्रौद्योगिकी उपायों, शोध संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, बेहतर जल प्रबंधन और विस्तार सेवाओं में सुधार के जरिए उत्पादकता बढ़ाई जा सके।

अध्ययन में नॉन-टैरिफ बाधाओं के नकारात्मक प्रभाव पर भी जोर दिया गया है और अनुपालन लागत घटाने तथा विवादों को कम करने का उपाय सुझाया गया है। इसके साथ ही एपीडा जैसी संस्थाओं की बड़ी भूमिका के बारे में भी चर्चा की गई है, जो विभिन्न उत्पादों के लिए ऐसे नियम-विनियम विकसित करे, जो वैश्विक रूप से स्वीकार्य हों और अपनाए जा सकें। अध्ययन में श्रेष्ठ कृषि पद्धतियां अपनाने के महत्त्व तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडा), कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, काजू निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यात निरीक्षण परिषद जैसी निर्यात संवर्धन संस्थाओं के समन्वय की जरूरत पर भी प्रकाश डाला गया है। अध्ययन के अनुसार, इनमें इस प्रकार के समन्वय की आवश्यकता है ताकि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर प्रयास किए जा सकें।

संदर्भः

- भारतीय निर्यात-आयात बैंक

एक्ज़िम बैंक ने गोंड एवं मधुबनी के कारीगरों को सहायता प्रदान की

जनवरी 2017 में बैंक ने ऑल इंडिया अर्टिजन्स एंड क्राफ्टवर्कर्स वेलफेयर असोसिएशन (एआईएसीए) तथा गोंड ट्राइबल ऑर्ट के साथ मिलकर गोंड तथा मधुबनी के दस-दस कारीगरों के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश में एक संयुक्त उत्पाद विकास कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य देशी तथा विदेशी बाजारों के लिए आधुनिक उत्पादों को तैयार करने हेतु परंपरागत शिल्प डिजाइनों का आदान-प्रदान करना था। कार्यशाला के दौरान गुणवत्तापूर्ण तथा उपयोगिता वाली वस्तुओं को तैयार करने के लिए बिहार तथा मध्य प्रदेश के कारीगरों ने कागज, कपड़े, लकड़ी, रबड़ तथा शीशा जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया। गोंड तथा मधुबनी मोटीफ कई उत्पादों जैसे लैम्प, पुस्तक, कार्ड होल्डर, कोस्टर, लैम्प शैड्स, तकिया कवर, बड़े-बड़े झोले तथा गिफ्ट बॉक्सों पर हाथ से छपाई की जाती है।

इन कारीगरों में पुरुष तथा महिलाएं दोनों शामिल थीं और महिलाओं में वैसी महिलाएं शामिल थीं जो कभी भी अपने गांवों से बाहर नहीं निकली हैं। इस कार्यशाला ने कारीगरों को बाजार से जुड़ने, उनकी प्रतिभा को एक नया आयाम देते हुए एक नई दृष्टि दी जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। जब फ्रांस के कला एवं पेंटिंग के कलक्टर ने कारीगरों के कला को सराहा तो उनका मनोबल और बढ़ गया। इस कार्यशाला में प्रथम गोंड आर्ट पेंटर स्व. श्री जांगढ़ सिंह श्याम की पत्नी श्रीमती ननखुशिया श्याम भी पधारी थीं।

उत्तर भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए बैंक को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) द्वारा बैंक को प्रदान किया गया।

केदारनाथ में बाढ़ से तबाही के बाद बाढ़ से प्रभावित परिवारों को स्थाई जीविकोपार्जन तथा महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जून 2015 में उत्तराखंड जिले के रूद्रप्रयाग में छह महीने का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन 30 महिला कारीगरों को सहायता प्रदान की गई जिनका आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। इस कार्यशाला में महिलाओं को स्टोल, स्कार्व तथा कार्पेट की बुनाई एवं कताई के लिए प्रशिक्षित किया गया।

बैंक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को पीआरएसआई द्वारा सराहा गया और प्रतिभागियों के समग्र विकास के लिए इस तरह के अन्य कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर आयोजित करने का अनुरोध किया गया।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: mas@eximbankindia.in

एक्ज़िमिअस शिक्षण केन्द्र की गतिविधियां
जनवरी-मार्च 2017

एक्ज़िम बैंक ने जनवरी-मार्च 2017 तिमाही के दौरान पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडी चैम्बर) के साथ मिलकर अफ्रीकी छात्रों के लिए मुंबई में 30 जनवरी, 2017 को एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का विषय थाः इंडिया-अफ्रीकाः आगे की राह। इस सेमिनार का उद्देश्य भारत और अफ्रीका के संबंधों को और प्रगाढ़ करना तथा सक्रिय सहभागिता के जरिए भावी हितधारकों को शामिल करते हुए भारत एवं अफ्रीका की भागीदारी के बारे में छात्रों को अवगत कराना तथा रोजगार अवसरों का सृजन करना था।

इस सेमिनार में उद्योग, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सामाजिक क्षेत्रों, राजनयिक एवं अकादमियों से वक्ताओं को बुलाकर भारत-अफ्रीका भागीदारी के संबंधों पर उनके अनुभवों को साझा किया गया।

इस सेमिनार में अफ्रीकी छात्र विशेषकर स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्र, भारतीय कारोबारियों के साथ-साथ मीडिया ने भी भाग लिया।

आगामी कार्यक्रमः

- भारतीय उद्योग संघ के साथ मिलकर 03 मई, 2017 को दिमापुर, नागालैंड में ''पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी व्यापार में अवसर एवं चुनौतियां'' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया तथा गंगटोक, सिक्किम में यह कार्यक्रम अभी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- भारतीय निर्यातक संगठन (फियो) के साथ मिलकर उदयपुर में 30 मई, 2017 को ''भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा'' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया।
- भारतीय निर्यात संगठन के साथ मिलकर लुधियाना में 18 जुलाई, 2017 को ''अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण'' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
- जुलाई-सितंबर 2017 के दौरान भारतीय निर्यातकों के लिए वाराणसी, रायपुर, भुवनेश्वर, इटानगर तथा इंफाल में कई निर्यात संवर्द्धन सेमिनारों का आयोजन प्रस्तावित है। एक्ज़िमिअस शिक्षण केन्द्र इन आगामी सेमिनारों के लिए कई क्षेत्रीय उद्योग संघों से संपर्क करेगा।

पुस्तक समीक्षा

सहायता से परेः संरचनात्मक रूपान्तरण के लिए विकासात्मक सहयोग

इस पुस्तक में संरचनात्मक परिवर्तन की दृष्टि से दक्षिण-दक्षिण विकास सहायता एवं सहयोग की पड़ताल करने के लिए नई संरचनात्मक अर्थव्यवस्था को सैद्धांतिक आधार बनाया गया है। यह जरूरी नहीं है कि आधिकारिक विकास सहायता हमेशा रियायती ही हो। इस पुस्तक में जस्टीन यीफु लिन तथा यान वांग ने इस मामले पर चीन के व्यापार निवेश मामलों पर विस्तार से चर्चा की है। इस पुस्तक के अनुसार संरचनात्मक परिवर्तन के लिए परंपरागत विकास सहायता अपर्याप्त है, इसलिए यह अप्रभावी भी है।

तुलनात्मक लाभों तथा किफायती आधार पर 'मल्टीपल विन' समाधानों के जरिए चीन तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों के सफल आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन कर तथा ब्राजील, भारत एवं अन्य ब्रिक्स देशों से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से नए उपायों एवं संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में 2015 के बाद की विकासपरक सहायता एवं सहयोग के नए रूप सहित इनकी परिभाषा पर लेखकद्वय द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है।

इस पुस्तक में बताया गया है कि 2015 से उभरती अर्थव्यवस्था विकास वित्त का प्रवाह पारंपरिक सहायता की अपेक्षा विकास-वित्त संस्थाओं, विकास बैंकों एवं संप्रभु निधियों से ज्यादा रहा है। वैश्विक स्तर पर उत्तर एवं दक्षिण के साथ भागीदारी कर चीन तथा अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं द्विपक्षीयवाद से बहुपक्षीयवाद की ओर बढ़ रही है। कुल मिलाकर इस पुस्तक में विदेशी विकास सहायता एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भूमिका को नए तरीके से दर्शाया गया है।

एक्ज़िम बैंक का 32वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान

भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा 1982 में बैंक के परिचालन के उपलक्ष्य में 1986 में स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान (सीडीएएल) श्रृंखला की शुरुआत की गई। तबसे प्रत्येक वर्ष बैंक द्वारा भारतीय तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में समकालीन विकास विषयों पर व्याख्यान देने के लिए किसी प्रसिद्ध वक्ता को आमंत्रित किया जाता है। इस व्याख्यान श्रृंखला से वैश्वीकरण पर बुद्धिजीवियों के बीच होने वाले चर्चा से लोग लाभान्वित होते हैं।

हाल के कुछ वर्षों में इस व्याख्यान श्रृंखला में पधारे प्रसिद्ध वक्ताओं में डॉ. जॉन लिप्स्की व, आईएमएफ के पूर्व प्रथम उप प्रबंध निदेशक; श्री सुपाचई पनिचपाकड़ी, अंकटाड के महासचिव; प्रो. निकालेस स्टर्न, मुख्य अर्थशास्त्री एवं विश्व बैंक के उपाध्यक्ष; लॉर्ड मेघनाद देसाई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर; रिटायर्ड माननीय जेम्स बॉल्गर, न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री; डॉ. केमल दर्विस, यूएनडीपी के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर; प्रो. जगदीश भगवती, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी; प्रो. यू यांगडिंग, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना सोसायटी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स; प्रो. प्रणब बर्धन, प्रोफेसर ऑफ ग्रेज्यूएट स्कूल एट द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले आदि हैं। अफ्रीकी विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड कबेरुका ने स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला 2016 में ''नए वैश्विक परिदृश्य में अफ्रीका-भारत निवेश को बढ़ावा'' विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

एक्ज़िम बैंक का 32वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान प्रोफेसर बैरी आयकनग्रीन द्वारा 27 मार्च, 2017 को ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई में दिया गया। प्रोफेसर आयकनग्रीन बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जो यहां 1987 से पढ़ा रहे हैं। इन्हें पेरिस में अमेरिकी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्राप्त है। इन्हें 2010 में इंटरनेशनल शुमपीटर सोसायटी से शुमपीटर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे 2011 में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के शीर्ष 100 ग्लोबल थिंकर्स में शामिल रहे हैं।

प्रोफेसर बैरी आयकनग्रीन ने पूंजी प्रवाहः क्या जानते हैं हम? विषय पर अपना व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान मुख्यतः उभरते बाजारों से और उभरते बाजारों को अंतरराष्ट्रीय पूँजी प्रवाह के प्रबंधन और 1990 के दशक से पूँजी के प्रवाह पर केन्द्रित था। व्याख्यान में सदी में आए बदलाव के साथ पूँजी खाते के उदारीकरण तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूँजी के इस प्रवाह को बाजारों में आए उतार-चढ़ाव, मुद्रायोजन और विनियमन ने कैसे प्रभावित किया पर विशेष चर्चा की गई।

अपने व्याख्यान में प्रोफेसर आयकनग्रीन ने कहा कि भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बाह्य वाणिज्यिक उधारियों सहित छोटी अवधि के ऋण प्रवाहों पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, जिसका तुलनात्मक महत्त्व कम ही सही, लेकिन हाल के वर्षों में बढ़ रहा है। भारत को देश से बाहर जाने वाले एफडीआई पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जो अन्य उभरते बाज़ारों की तुलना में ज़्यादा है और जहां नियम व्यक्तियों के बजाय कॉर्पोरेट के लिए अधिक उदार हैं।

उन्होंने कहा कि ''भारत निश्चित रूप से बीते 25 वर्षों में अपने पूँजी खाते को धीरे-धीरे सावधानीपूर्वक और वृद्धिशील रूप से उदार करता रहा है। भारत ने सावधानी बरती कि आउटफ्लो से पहले इनफ्लो का उदारीकरण किया और इसमें भी सबसे पहले एफडीआई इनफ्लो, इसके बाद पोर्टफोलियो इक्विटी इनफ्लो, फिर पोर्टफोलियो ऋण इनफ्लो और आख़िर में आउटफ्लो का उदारीकरण किया तथा ट्रांजैक्शन की ऊपरी सीमा बढ़ाई और इसका दायरा बढ़ाकर ऑटोमैटिक मंजूरी तक किया।''

प्रोफेसर आयकनग्रीन ने सुझाव दिया कि भारत पूँजी खाते में ट्रांजैक्शन पर क्वांटिटेटिव नियंत्रण के विपरीत क़ीमत-आधारित नियंत्रण की दिशा में बढ़ सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश को अपना बैंकिंग सिस्टम और मज़बूत करने की ज़रूरत है ताकि बैंक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक जिनकी निम्न आस्ति गुणवत्ता और गवर्नेंस संबंधी मसले हैं, वे अस्थिरता की स्थिति से बेहतर तरीके से निपट सकें और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह बढ़ सके।

उन्होंने कहा कि ''हालिया अनुभवों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पूँजी प्रवाह अस्थिर हैं। इसलिए भुगतान संतुलन के पूँजी खाते का उदारीकरण धीरे-धीरे ही किया जाना चाहिए। और इस बीच घरेलू वित्तीय बाज़ार और संस्थानों को मज़बूत बनाने के अन्य उपाय किए जाने चाहिए। पहले एफडीआई को प्रभावित करने वाले विनियमनों में ढील दी जानी चाहिए, क्योंकि एफडीआई सबसे कम अस्थिरता वाला पूँजी प्रवाह है।'' प्रोफेसर आयकनग्रीन का मानना है कि जब सकल एफडीआई इनफ्लो से बड़े चालू खाता घाटे को संतुलित किया जाता है तो एफडीआई इनफ्लो में सीमित गिरावट भी समस्या पैदा कर सकती है। उभरते बाज़ारों से एफडीआई आउटफ्लो, हाल के वर्षों में और महत्त्वपूर्ण हो गया है, जो पूँजी पलायन का कारण बन सकता है, जैसा कि चीन में हुआ। और इस समस्या से निपटने के लिए चीन को देश से बाहर जाने वाले एफडीआई को आसान बनाने वाले उपाय वापस खींचने पड़े।

प्रोफेसर आयकनग्रीन ने अपने व्याख्यान के सारांश में कहा कि तमाम दूसरी चुनौतियों के बावजूद पूँजी खाते के उदारीकरण संबंधी ज़रूरी सुधारों के मामले में भारत की यह कहानी काफी सकारात्मक रही है।

सीएलएमवी देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंध बढ़ाना

अपने मजबूत विनिर्माण आधार के चलते आसियान क्षेत्र विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र बन चुका है। क्षेत्र का वर्तमान कारोबारी आधार कच्चे माल की खरीद और उसके बाद यहाँ से तैयार माल बेचने पर आधारित है। आसियान क्षेत्र के सीएलएमवी (कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम) देशों में भविष्य में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए वैश्विक आर्थिक समुदाय का आकर्षण इस ओर बढ़ना शुरू हो गया है।

2015 के आंकड़ों के अनुसार सीएलएमवी क्षेत्र पूरे आसियान क्षेत्र के 32% क्षेत्र, 26% जनसंख्या और 12% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। सीएलएमवी क्षेत्र का जीडीपी 2015 में 7.1% की सी ए जी आर के साथ बढ़ा जबकि इसी दौरान पूरे आसियान क्षेत्र की वृद्धि दर 4.8% रही।

सीएलएमवी क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय वस्तु व्यापार

आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफ टी ए) की स्थापना के बाद सीएलएमवी क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय वस्तु व्यापार काफी तेजी से बढ़ रहा है। इससे अंत: क्षेत्रीय व्यापार में भी मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टियों से बढ़ोत्तरी हुई है। आसियान के कुल व्यापार में सीएलएमवी क्षेत्र का हिस्सा 2005 के 6.7% से बढ़कर 2015 में 17.4% हो गई है। इसी प्रकार आसियान के कुल निर्यातों में सीएलएमवी क्षेत्र का हिस्सा 2005 के 6.1% से बढ़कर 2015 में 16.2% और आयात में हिस्सा 2005 के 7.3% से बढ़कर 2015 में 18.7% हो गया है। इसके बावजूद सीएलएमवी देशों के अंदर व्यापार में काफी भिन्नताएँ हैं। उदाहरण के लिए आसियान के कुल व्यापार में केवल वियतनाम का हिस्सा 2014 में 14.5% रहा जबकि कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार का कुल मिलाकर हिस्सा 3% रहा। वियतनाम से बढ़ते निर्यात के चलते ही सीएलएमवी क्षेत्र का 2015 में कुल निर्यात 2014 के 185.9 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2015 में 187.8 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। 2005 से 2015 की अवधि के दौरान सीएलएमवी क्षेत्र का कुल निर्यात 2005 के 39.9 बिलियन यूएस डॉलर से लगभग पाँच गुना बढ़कर 2015 में 187.8 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जो आसियान के कुल निर्यात में 2005 में 6.1% से 2015 में 16.2% का हिस्सा प्रदर्शित करता है।

सीएलएमवी क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार

आसियान क्षेत्र वाणिज्यिक सेवाओं का निवल आयातक है। वर्ष 2015 में कुल वैश्विक सेवाओं के आयात में जहां इसका 6.7 प्रतिशत हिस्सा रहा वहीं निर्यात में 6.4 प्रतिशत हिस्सा रहा। सीएलएमवी क्षेत्र में वियतनाम को छोड़कर अन्य सभी देश सेवाओं के निवल निर्यातक हैं।

कंबोडिया से सेवाओं का निवल निर्यात वर्ष 2010 के 1.9 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2015 में 3.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया जो मुख्यत: मजबूत पर्यटन क्षेत्र के चलते रहा। इसी अवधि के दौरान कंबोडिया से सेवाओं का निवल आयात वर्ष 2010 के 0.9 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2015 में 1.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया।

इसी प्रकार लाओ पीडीआर से सेवाओं का निवल निर्यात वर्ष 2010 के 0.5 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2015 में 0.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया तथा इसी अवधि के दौरान सेवाओं का नेट आयात वर्ष 2010 के 0.3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2015 में 0.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया।

इसी प्रकार म्यांमार से वाणिज्यिक सेवाओं का निवल निर्यात वर्ष 2010 के 0.3 बिलियन यूएस डॉलर से 12 गुना बढ़कर 2014 में 4.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया जो मुख्यत: मजबूत पर्यटन क्षेत्र के चलते रहा। इसी अवधि के दौरान सेवाओं का नेट आयात वर्ष 2010 के 0.3 बिलियन यूएस डॉलर से तीन गुना बढ़कर 2015 में 2.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया।

वियतनाम सीएलएमवी क्षेत्र में वाणिज्यिक सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा आयातक है। वियतनाम से वाणिज्यिक सेवाओं का निवल निर्यात वर्ष 2010 के 7.4 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2015 में 11.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। इसी अवधि के दौरान सेवाओं का निवल आयात वर्ष 2010 के 9.8 बिलियन यूएस डॉलर से 2015 में 15.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया।

सीएलएमवी देशों में एफ डी आई

सीएलएमवी देशों को हाल के वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एफ डी आई का काफी फायदा मिला है। सीएलएमवी क्षेत्र में कुल एफ डी आई आवक वर्ष 2005 के 2.5 बिलियन यूएस डॉलर से सात गुना बढ़कर 2015 में 17.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। इसी प्रकार क्षेत्र से एफ डी आई जावक वर्ष 2005 के 65.3 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2015 में 1.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। वर्ष 2015 में आसियान को कुल एफ डी आई आवक में सी एल एम वी क्षेत्र का 14 प्रतिशत हिस्सा रहा जिसमें से अकेले वियतनाम का 9.4 प्रतिशत हिस्सा रहा उसके बाद म्यांमार का 2.2 प्रतिशत तथा कंबोडिया का 1.4 प्रतिशत और लाओ पी डी आर का 1 प्रतिशत हिस्सा रहा। हालांकि क्षेत्र से एफ डी आई जावक निम्न स्तर

पर रहा। आसियान से कुल एफ डी आई जावक में सी एल एम वी क्षेत्र का 1.7 प्रतिशत हिस्सा रहा और यह मुख्यत: वियतनाम से रहा।

सीएलएमवी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय निवेश और व्यापार संबंध

पिछले 10 सालों में सीएलएमवी क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार वर्ष 2005 के 1.4 बिलियन यूएस डॉलर से सात गुना बढ़कर 2015 में 10.3 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है। सीएलएमवी क्षेत्र भारत का निर्यात वर्ष 2005 के 0.8 बिलियन यूएस डॉलर से आठ गुना बढ़कर 2015 में 6.4 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है जो आसियान को भारत के कुल निर्यात का 24.3 प्रतिशत हिस्सा है। इसी प्रकार सीएलएमवी क्षेत्र से भारत का कुल आयात वर्ष 2005 के 0.6 बिलियन यूएस डॉलर से छह गुना बढ़कर 2015 में 3.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है जो आसियान से भारत के कुल आयात का 9.4 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2015 में सीएलएमवी क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार अधिशेष 2.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा। सीएलएमवी देशों में जहाँ वियतनाम और कंबोडिया के साथ भारत का व्यापार अधिशेष रहा वहीं म्यांमार और लाओ पी डी आर के साथ व्यापार घाटा रहा। म्यांमार के साथ व्यापार घाटा मुख्य रूप से खाद्य वनस्पति तेल और अन्य रूट्स तथा ट्यूबर्स के चलते रहा वहीं लाओ पी डी आर के साथ व्यापार घाटा मुख्य रूप से अयस्क, स्लैग तथा ऐश के आयात के चलते रहा।

हाल के वर्षों में व्यापार के साथ-साथ सीएलएमवी क्षेत्र में भारतीय निवेश को भी काफी बढ़ावा मिला है। इस क्षेत्र का तेजी से बढ़ता बाजार, सस्ता श्रम और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन यहाँ भारतीय निवेश को आकर्षित करने का प्रमुख कारण रहा है। अप्रैल 1999 से दिसंबर 2016 के दौरान संयुक्त उद्यमों और अनुषंगियों के जरिए इस क्षेत्र में भारतीय निवेश 772.7 मिलियन यूएस डॉलर रहा। इसमें से अधिकांश निवेश (सीएलएमवी क्षेत्र का 66.5%) से वियतनाम को रहा। अप्रैल 1999 से दिसंबर 2016 के दौरान इस क्षेत्र का भारत में निवेश काफी कम 13.6 मिलियन यूएस डॉलर रहा। इसमें से अधिकांश निवेश म्यांमार से रहा।

सीएलएमवी देशों के साथ भारत के व्यावसायिक संबंध बढ़ाने की रणनीतियाँ

आसियान क्षेत्र में भारत के आर्थिक रुचि बीते कुछ वर्षों में बढ़ी है हमारा 'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' नीति की ओर बढ़ना इसका प्रमाण है। आसियान क्षेत्र में भी विशेष रूप से सीएलएमवी देशों में आर्थिक विकास अलग-अलग स्तरों पर है। शोध अध्ययन में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में अवसर तो बहुतायत में हैं, लेकिन इन देशों में भारतीय उद्यमियों के प्रयास सीमित हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यू के से कई कंपनियां यहाँ पहले से ही मौजूद हैं और कुछ ने यहाँ अपनी पैठ बनाने की योजना शुरू कर दी है। सीएलएमवी देशों में भारत के व्यावसायिक संबंध बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन विकास, वित्तीय सेवाओं, आईटी आधारित सेवाओं, क्षेत्रीय वेल्यू चेन, कनेक्टिविटी में सुधार और एसएमई क्षेत्र में सहयोग के साथ निवेश को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों/ वाणिज्य संगठनों जैसी संस्थाओं से संबंध विकसित करना प्रमुख रणनीतियां हो सकती हैं।

चौथी इंडिया-सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव

चौथी इंडिया-सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव राजस्थान के जयपुर में 27-28 फरवरी, 2017 को हुई। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय कारोबारियों को सी एल एम वी क्षेत्र के चारों देशों की सरकारी प्रतिनिधियों और कारोबारियों को एक मंच पर लाकर उनके बीच संवाद बढ़ाना है ताकि सी एल एम वी क्षेत्र के निर्णयकर्ता विभिन्न क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग, इंजीनियरिंग, कंसलटेंसी, और निर्माण गतिविधियों में संलग्न भारतीय कंपनियों से सीधे कारोबारी बातचीत कर सकें।

एक्ज़िम बैंक का प्रकाशन 'सीएलएमवी देशों के साथ भारत के व्यावसायिक संबंधः आसियान बाजारों का प्रवेश द्वार' राजस्थान के जयपुर में 27 फरवरी, 2017 को हुई चौथी इंडिया-सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव के दौरान जारी किया गया।

शोध अध्ययन में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में अवसर तो बहुतायत में हैं, लेकिन इन देशों में भारतीय उद्यमियों के प्रयास सीमित हैं। शोध अध्ययन में आसियान के संदर्भ में सीएलएमवी देशों में भारत के व्यावसायिक संबंध बढ़ाने के लिए प्रमुख रणनीतियों को रेखांकित किया गया है।

संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यूएस डॉलर)	**1365.4**	**1708.5**	**1823.0**	**1829.0**	**1863.2**	**2042.4**	**2073.7[f]**	**2230.8[f]**
प्रति व्यक्ति जीडीपी	**1146.7**	**1411.7**	**1482.1**	**1462.9**	**1466.4**	**1581.6**	1579.8f	**-**
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	**8.6**	**8.9**	**6.7**	**5.5****	**6.4****	**7.5****	**8.0****	**7.1p****
जीडीपी में क्षेत्रगत हिस्सा (%)	**8.6**	**8.9**	**6.7**	**5.5****	**6.4****	**7.5****	**8.0****	**7.1p****
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	14.6	14.6	18.5	17.8**	17.5**	16.3**	15.3[p]**	15.0[ae]**
उद्योग	28.3	27.9	32.5	31.9**	31.5**	31.2**	31.2[p]**	30.8[ae]**
सेवाएं	57.1	57.5	49.0	50.3**	51.0**	52.5**	53.5[p]**	54.3[ae]**
मुद्रास्फीति दर (सीपीआई, वार्षिक औसत %)	12.2	10.4	8.3	10.2	9.5	5.9	4.9	3.8**
मुद्रास्फीति दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	3.8	9.6	8.9	7.4	6.0	2.0	-2.5	1.7**
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	**6.5**	**4.8**	**5.9**	**4.9**	**4.5**	**4.1**	**3.9[e]**	**3.5[e]**
विनिमय दर (₹/यूएस डॉलर, औसत)	47.4	45.6	47.9	54.4	60.5	61.1	65.5	67.1
विनिमय दर (₹/यूरो, औसत)	67.1	60.2	65.9	70.1	81.2	77.5	72.3	73.6
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**178.8**	**249.8**	**306.0**	**300.4**	**314.4**	**310.3**	**262.3**	**276.5**
% परिवर्तन	*-3.5*	*39.8*	*22.5*	*-1.8*	*4.7*	*-1.3*	*-15.5*	*5.4*
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**28.2**	**36.4**	**56.7**	**60.9**	**63.2**	**56.7**	**30.6**	**31.6**
% परिवर्तन	*2.3*	*29.0*	*55.9*	*7.3*	*3.8*	*-10.2*	*-46.1*	*3.4*
गैर–तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**150.6**	**213.4**	**249.2**	**239.5**	**251.2**	**253.6**	**231.7**	**244.9**
% परिवर्तन	*-4.6*	*41.8*	*16.8*	*-3.9*	*4.9*	*0.9*	*-8.6*	*5.7*
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**288.4**	**369.8**	**489.3**	**490.7**	**450.2**	**448.0**	**381.0**	**382.7**
% परिवर्तन	*-5.1*	*28.2*	*32.3*	*0.3*	*-8.3*	*-0.5*	*-15.0*	*0.5*
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**87.1**	**106.0**	**155.0**	**164.0**	**164.8**	**138.3**	**82.9**	**86.9**
% परिवर्तन	*-7.0*	*21.6*	*46.2*	*5.9*	*0.4*	*-16.0*	*-40.0*	*4.7*
गैर–तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**201.2**	**263.8**	**334.3**	**326.7**	**285.4**	**309.7**	**298.1**	**295.9**
% परिवर्तन	-4.2	31.1	26.7	-2.3	-12.6	8.5	-3.8	-0.7
व्यापार संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)	**-109.6**	**-120.0**	**-183.3**	**-190.3**	**-135.8**	**-137.7**	**-118.7**	**-106.2**
सेवा निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)* **	**96.0**	**124.6**	**140.9**	**145.7**	**151.8**	**158.1**	**154.3**	**163.1**
*सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)****	49.7	53.1	62.2	65.9	69.4	73.1	74.2	73.7
सेवा आयात (बिलियन यूएस डॉलर)* **	**60.0**	**80.6**	**76.9**	**80.8**	**78.7**	**81.6**	**84.6**	**95.7**
सेवा संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)***	36.0	44.0	64.0	64.9	73.1	76.5	69.7	67.4
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	**-38.4**	**-47.9**	**-78.2**	**-87.8**	**-32.4**	**-26.8**	**-22.1**	**-15.2**
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष (%)	*-2.8*	*-2.8*	*-4.2*	*-4.8*	*-1.7*	*-1.3*	*-1.1*	*-0.7*
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	**279.1**	**304.8**	**294.4**	**292.0**	**304.2**	**341.6**	**360.2**	**370.0**
विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	**260.9**	**317.9**	**360.8**	**409.4**	**446.2**	**474.7**	**485.0**	**471.9**
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	18.2	18.2	20.5	22.3	23.9	23.2	23.4	20.2
अल्पावधि ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	52.3	65.0	78.2	96.7	91.7	85.5	83.4	88.0
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	20.1	20.4	21.7	23.6	20.5	18.0	17.2	18.6
कुल ऋण सेवा का अनुपात (%)	5.8	4.4	6.0	5.9	5.9	7.6	8.8	8.3
एफडीआई (बिलियन यूएस डॉलर)	**37.7**	**36.0**	**46.6**	**34.3**	**36.0**	**45.1**	**55.6**	**60.0**
जीडीआर/एडीआर (बिलियन यूएस डॉलर)	3.3	2.0	0.6	0.2	0.02	1.3	0.4	-
एफआईआई (नेट) (बिलियन यूएस डॉलर)	29.0	29.4	16.8	27.6	5.0	40.9	-4.0	7.7
एफडीआई जावक (बिलियन यूएस डॉलर)	**15.1**	**17.2**	**10.9**	**7.1**	**9.2**	**4.0**	**8.9**	**7.0**

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक; केन्द्रीय बजट, आर बी आई मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट और साप्ताहिक सांख्यिकीय सप्ली; वित्त मंत्रालय; सी एस ओ; ईआईयू; नैसकॉम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आई आई एफ), डब्ल्यू ई ओ, आई एम एफ.

नोटः भारत सरकार के अनुमान; पी– ई ए सी, भारत सरकार के अस्थाई अनुमान; एफ – आई आई एफ अनुमान; –उपलब्ध नहीं; –आई आई एफ अनुमान; –% गत वर्ष की तुलना में वर्तमान अवधि में परिवर्तन; – उपलब्ध नहीं; ** संशोधित आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार डेटा; – पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वृद्धि

व्यापार और भागीदारी अवसर

व्यापार अवसर

गारमेंट फैब्रिक्स

राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित कंपनी, जो 1971 में बनी। हर साल यहां 18 लाख मीटर फैब्रिक का उत्पादन होता है। कंपनी में अलग-अलग किस्म के फैब्रिक बनते हैं, जैसे- पॉली विस्कोस, ऊनी। इसके अलावा फर्निशिंग तथा फैशन के लिए ऊन, लाइक्रा, सिल्क और लिनेन आदि में भी फैब्रिक उपलब्ध कराती है।

कचरा प्रबंधन

ठोस कचरा प्रबंधन में जरूरत के अनुसार सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी बायोगैस संयंत्र और मदजल शोधन संयंत्र (वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) बनाती है। कंपनी ने फ्रांस की एक कंपनी से प्रौद्योगिकी के लिए टाई-अप किया है।

ऑर्गैनिक और वन उत्पाद

यह एक लघु स्तरीय उद्यम है, जो ऑर्गैनिक उत्पाद एकत्रित कर रहा है। इसके उत्पाद वर्ल्ड फैयर ट्रेड ऑर्गैनाइजेशन (डब्ल्यूएफटीओ) के मानकों पर खरे उतरे हैं और यह विभिन्न तरह के ऑर्गैनिक खाद्य और बॉडी केयर उत्पाद बनाता है।

फर्नीचर

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार एक्सपोर्ट हाउस विभिन्न प्रकार की शिल्पकृतियां, फर्नीचर और सजावटी सामान बनाता है। राजस्थान के जोधपुर में स्थित यह एक्सपोर्ट हाउस औद्योगिक फर्नीचर के साथ लोहे और लकड़ी के फर्नीचर तथा मार्बल की शिल्पकृतियां भी बनाता है।

ऊन तथा ऊनी उत्पाद

बेहतर जीवनशैली बनाए रखने वाली बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करते हुए यह कंपनी ऐसे टेक्सटाइल के निर्माण में संलग्न है, जिसे पुनः नवीकृत कर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भेड़ की ऊन जैसे प्राकृतिक फाइबर का इस्तेमाल कर इरि सिल्क फाइबर और सिल्क ऊन मिश्रित धागे बनाती है।

होम फर्नीशिंग

हिमालय की तलहटी में हाथ से बनी रजाइयां, कुशन, ध्वजपट और बच्चों के अन्य सामान। ये उत्पाद एक एनजीओ के मार्गदर्शन में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं।

तैयार मसाले

यह 1965 में बना हिमाचल प्रदेश स्थित भारतीय मसालों का ब्रांड है, जो तैयार (रेडी-टू-कुक) मसालों के मिश्रण बनाता है। इन मसालों के जरिए खाना बनाते समय नमक, प्याज, अदरक या दूसरे कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं रह जाती है।

डीजल इंजन

1965 में स्थापित यह कंपनी अग्रणी डीजल इंजन, जेनरेटर, वेल्डिंग सेट, पानी के पंप और पंपिंग सेट बनाती है, जो ज्यादातर खेती-बाड़ी, उद्योगों, घरों और सामान्य जरूरत के समय काम में आते हैं।

होम फर्नीशिंग और गारमेंट

उदयपुर का एक सामाजिक उद्यम, जो फेअर ट्रेड फोरम-भारत और डब्ल्यूएफटीओ एशिया का सदस्य है। यह कुर्ते, साड़ियां, घर की सजवाट का सामान और फैशन एक्सेसरीज बनाता है। इसके सभी उत्पादों को प्रामाणिक क्राफ्ट मार्क प्रमाणपत्र प्राप्त है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉल करें - फ़ोन: 2217 2600, विस्तार: 2707/2737, फ़ैक्स: 2218 8268, ई-मेल: mas@eximbankindia.in